वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

सितंबर, 2019

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

100 दिनों की पहल व उपलब्धियां

भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया तथा व्यापार को प्रोत्साहन एवं निर्यात को बढ़ावा

इन्वेस्ट एंड मेक इन इंडिया

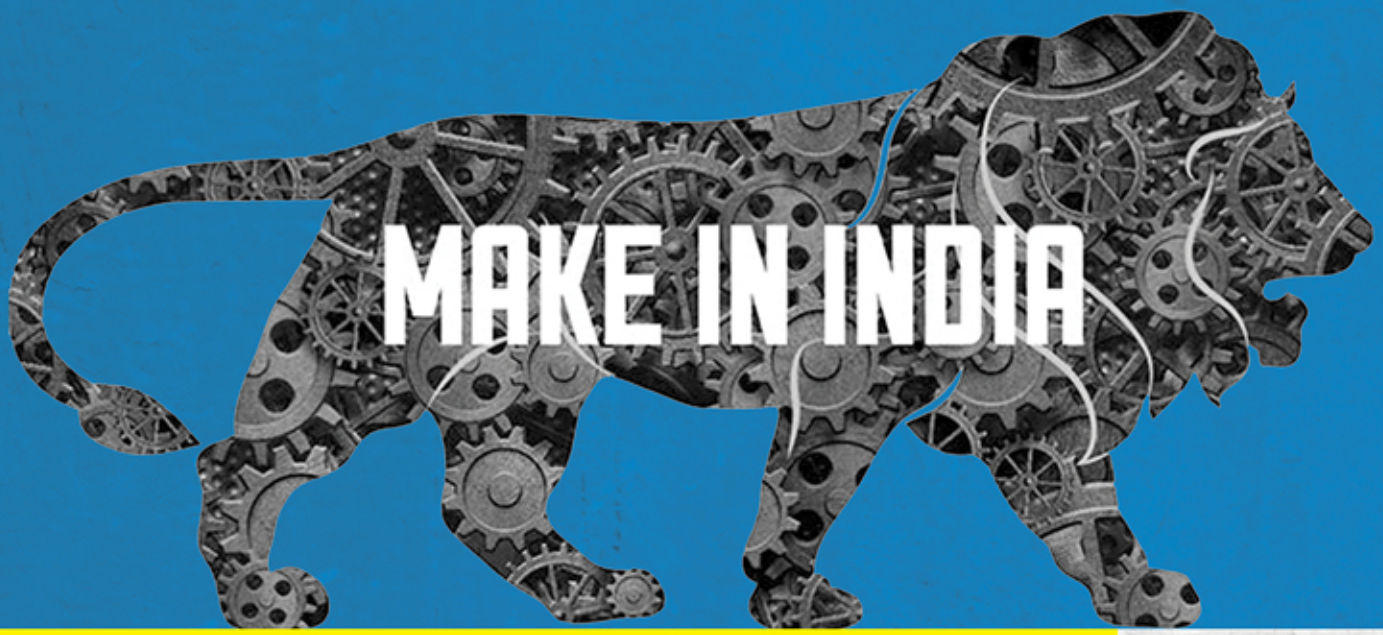

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा

संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना और अनुबंध विनिर्माण सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (SBRT) एंटिटी की प्रक्रिया को सरल तथा अधिक लचीली बनाया गया

निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2019

ट्रस्टों और किसी अन्य अधिसूचित योग्य संस्था को एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने में सक्षम करेगा

एसईजेड में ज़मीन के लिए 30 साल की लीज की ऊपरी सीमा हटाई गई

नवीनता को बढ़ावा

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में 2015 में रैंक 81 से 2019 में रैंक 52 का सुधार- पिछले 4 वर्षों में किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था द्वारा सबसे बड़ी छलांग

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (संशोधन) अधिनियम 2019, राज्यसभा में पारित हुआ और अगले सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में 4 नए एनआईडी घोषित करता है

एनआईडी, मध्य प्रदेश और एनआईडी, असम ने 29 जुलाई 2019 से एकेडमिक सेशन शुरू किया

व्यापार को बढ़ावा

व्यापारियों के मुद्दों के समाधान के लिए
नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशेष रूप
से आरक्षित 50 लाख रुपये तक की खरीद
(कुछ मामलों में छोड़कर)

नीलामी डॉक्यूमेंट्स में घरेलू सप्लायर्स के विरुद्ध
भेदभाव करने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक एक्शन
लेना अधिकृत किया गया

इज ऑफ डूइंग बिजनेस

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय नीति - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों की सुविधा के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया

लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा

नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, 2019 की मंजूरी के लिए उसको अंतिम रूप दिया गया

जो कुल लॉजिस्टिक्स लागत को देश के जीडीपी के 14% से गिरा कर 9% में लाएगी

जो प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और भारत को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाएगी

मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्ज़ बिल 2019 की मंजूरी के लिए उसको अंतिम रूप दिया गया

जो निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार के लिए माल की आवाजाही को सुगम बनाता है

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए कौशल

पहली बार, कौशल विकास के लिए 23 क्वालिफिकेशन पैक्स विकसित और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल विकास प्रदान करने के लिए उनको अंतिम रूप दिया गया

निर्यात को बढ़ावा

चुनौतीपूर्ण बाजारों में निर्यात में सहायता के लिए धन की व्यवस्था

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) में रु 389 करोड की व्यवस्था और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट (NEIA) में रु 300 करोड़ का योगदान

ईसीजीसी के साथ पारदर्शिता के माध्यम से निर्यातकों के दावों को आसान बनाना - सभी लंबित दावों को सार्वजनिक उपयोग के लिए ऑनलाइन रखा गया है

सभी निर्यातकों को सस्ती ऋण तक पहुँच देने की योजना को अंतिम रूप दिया गया

हमारे निर्यातकों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, आशयित लाभों की बेहतर प्राप्ति और बाजार अंतराल में पहुंच को संबोधित करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंटस (FTAs) की समीक्षा की शुरुआत

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज (RoSCTL) की मंजूरी के लिए उसको अंतिम रूप दिया गया

भारतीय व्यवसायों और रोजगार को बढ़ावा

प्रतिबंधित सूची में डालकर अगरबत्ती आयात को सुव्यवस्थित और विनियमित किया गया

आयात वृद्धि को संबोधित करने और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए ताड़ के तेल पर उपयुक्त सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई

स्टार्टअप को बढ़ावा

स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय रियायतें। विस्तारित लाभ जैसे 'एंजल टैक्स' मुद्दे, लॉसेस का कैरी फॉरवार्ड एंड सेट ऑफ, इग्ज़िम्प्शन फ्रॉम सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आदि बजट 2019-20 में पेश किए गए

पहला ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी: ऑरिक सिटी

ऑरिक सिटी का उद्घाटन 7 सितंबर 2019 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।

ऑरिक सिटी को दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र राज्य में 10,000 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया गया है।

प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों में सिटी-वाइड वाई-फाई, मल्टी-सर्विस डिजिटल कियोस्क, कुशल इ-गवर्नेंस सिस्टम्स और यूजर-फ्रेंडली चैटबॉट शामिल हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों की रेलवे और एयरवेज से निकटता के साथ, यह निर्यात उन्मुख व्यवसायों के लिए आदर्शपूर्ण हैं। सेंट्रल गवर्नेंस सिस्टम व्यापार में पारदर्शिता और आसानी प्रदान करता है।